

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: मार्च 24 2008

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:599/XVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक द्वारा समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को मदरसा अरबी फारसी बोर्ड द्वारा परीक्षा के संचालन हेतु आयोजनागत पक्ष रु0. 5,00,000.00(रुपया पांच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान

संख्या-15 तथा आयोजनेत्तर अधिकां आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

5. वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित करें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययिता/अवचनबद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लिया जाय।
7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
10. समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध करायें।
11. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय के "अनुदान संख्या-15 में आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ-00-800-अन्य व्यय-15-मदरसा अरबी फारसी बोर्ड-00-" के मानक मद 20-सहायक अनुदान /अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जायेगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या: 136(P)/xxviii(3)/08 दिनांक 13.03.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 155/XVII(1)-3/06-7(11) 2007टी0सी0, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. कोषाधिकारी, हल्द्वानी(नैनीताल) उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा, से

(धीरेन्द्र सिंह/क्ताल)
उपसचिव।